



आपकी सफलता का प्रवेश द्वार कौटिल्य एकेडमी



AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED INSTITUTE

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान

सामान्य अध्ययन / GENERAL STUDIES

निर्धारित समय: 3 hour
Time Allowed: _____

अधिकतम अंक 300
Maximum Marks _____

नाम. Name : Akanksha Gargwal

मोबाईल नं. Mobile No : 7703837099

ईमेल पता. E-mail Address : akankshagargwal94@gmail.com

रोल नं. Roll No : _____ दिनांक (Date) 15/Jan/2021

परीक्षा का माध्यम
(Medium of Exam) हिन्दी
विद्यार्थी के हस्ताक्षर
(Student's Signature) Akanksha

प्रश्न - पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें :

इसमें 3 प्रश्न हैं तथा सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सामा, जहा विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।

उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

Question Paper Specific Instructions

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions :

There are 3 question and all the questions are compulsory.

The Number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answer must be written in the medium authorized in the admission certificate which must be started clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) booklet in the space provide.

No marks will be given for answer written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the answer book must be clearly struck off.

कुल प्राप्तांक (Total Marks Obtained) _____ टिप्पणी (Remarks) _____

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

A

ऐसा संघर्ष जिसे केन्द्र के पास अधिक शक्तियां होते हुए भी केन्द्र-राज्य मध्य शक्ति पृथक्करण सिद्ध होना चाहिए।
 भारत में यह संघर्ष मौजूद है।

B

सीनेट अमेरिका का उच्च सदन है जो भारत के राज्यसभा के समतुल्य सदन माना जाता है।

D

अनुच्छेद 32 के तहत परमादेश में उच्च अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों से उनके कार्यों के बारे में पूछा जाता है।

C

E

F

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

G यह पद 1967 में सृजित किया गया। सामान्यतः विपक्ष नेता
लोकसभा समिति का अध्यक्ष होता है एवं कई संसदीय
समितियों से संबन्धित होता है।

H अनुच्छेद 323(क) के तहत प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन, भत्ते,
पद आदि संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु अधिकृत हैं। इसके
अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

I
J 14(ए) -

K मानव अधिकार अधिनियम 1993 के तहत गठित आयोग है जिसमें
एक अध्यक्ष सहित अन्य सदस्य होते हैं। यह एक संवैधानिक
आयोग है जो मानव अधिकार संबंधित कसम उठाता है।

L अनुच्छेद 335 सैन्य क्षेत्र सेवा आयोग, राज्य कोषसेवा आयोग
आदि सार्वजनिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्गों के
भ्रारक्षण से संबंधित हैं।



प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
 (Mains Answer Sheet)

M

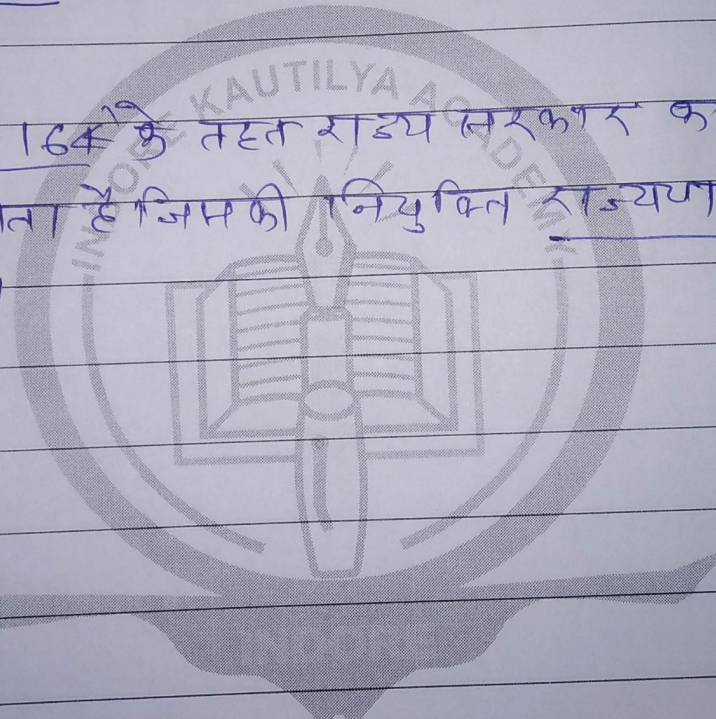
भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क मतदाता के निर्वाचन में मत डालने हेतु यह कोरो पहचान पत्र प्रदान किया जाता है।

H

ऐसा संगठन जो बिना किसी निजी लाभ व संगठन द्विसे परिपूर्ण होकर सामाजिक उद्देश्यों हेतु गठित किया जाता है। जैसे - सेवा, भादि।

Q

यह अनुच्छेद 164 के तहत राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है जिसे की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।



मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

2 A

अनुच्छेद 360 के तहत देश में या किसी राज्य में वित्तीय स्थिति में असंतुलन होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल लागू करा जा सकता है। इसके अन्तर्गत:

- प्रमुख प्राधिकारियों, लोकसेवकों, सांसदों, विधायकों के वेतन भत्तों में उचित कटौती की जा सकती है।
- राज्य वित्त बजट संबंधी प्रावधानों हेतु राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य हो जाती है।
- राज्य विधानमंडल वित्त संबंधी विधेयक आदि राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित एवं अनुमति से ही पारित किये जायेंगे।
- राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्रीय बैंक संबंधी प्रक्रियाओं पर भी नियंत्रण लगाया जा सकता है।

वस्तुतः भारत में वर्तमान तक तब वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया

2 D

कुछ निश्चल महिला व पुरुषों का एक सामाजिक-आर्थिक समूह जो आर्थिक गतिविधि एवं जीवन शैली के सुचारु रूप से लपकने हेतु गठित किया जाता है।

- यह समूह बैंक गतिविधि व इससे संबंधित लोगों के महत्वपूर्ण अंतर को कम करता है।
- वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय जागरूकता को प्रोत्साहित।
- महिला स्वयं सहायता समूह महिला लक्ष्यकर्मियों में लक्ष्यकर्मियों को प्रोत्साहन एवं आर्थिक स्थिति बेहतर करने हेतु निश्चल।
- संगठन कार्यप्रणाली एवं विकास दर वृद्धि में सहायक निश्चल ही यह एक अग्रगामी कदम है परन्तु उत्पाद

वस्तुतः तकनीक अभाव से यह समूह अपने वास्तविक उद्देश्यों को पाने में अक्षी पीड़े है।



मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं

- 1) सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना।
- 2) केन्द्र - राज्य संबंध संबंधी प्रावधान एवं शक्ति पृथक्पृथक् का सिद्धांत।
- 3) केन्द्र में द्वैध शासन की स्थापना।
- 4) संघीय न्यायपालिका की स्थापना।
- 5) संविधान सर्वोच्चता का सिद्धांत एवं संघ के स्तर पर राज्यों का प्रतिनिधित्व।
- 6) शक्ति पृथक्पृथक् के तहत संघ, राज्य एवं सम्बन्धी स्तर का निर्धारण।

क) इस अधिनियम कि कई प्रावधान वर्तमान संविधान में परिष्कृत होते हैं यह एक आधारभूत अधिनियम है संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद को

अनुच्छेद 368 के तहत प्राप्त है जिसके अन्तर्गत संसद किसी विधेयक को लाधारण बहुमत, विशेष बहुमत एवं विशेष बहुमत व आद्ये से अधिक राज्यों के समर्थन से पारित कर संशोधित कर सकती है। संसद की यह शक्ति असीमित नहीं है वस्तुतः न्यायपालिका के पुनराविष्ठाउन के अन्तर्गत आती है। न्यायपालिका संविधान की मूल भावना या बुनियादी ढांचे में उल्लंघन के मद्देनजर इस शक्ति के तहत संशोधन को अमल्य घोषित कर सकती है।

निष्कर्षतः संविधान संशोधन जो संसद की एक अहम शक्ति है पर भी नियंत्रण लगाया जा सकता है।

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका (Mains Answer Sheet)

G

भारत का संविधान संघीय विशेषताओं एवं एकात्मकता दोनों से युक्त है जहां शक्तिशास्त्री के साथ संसुक्तकारी राज्य का सम्बन्ध है। प्रमुख एकीकरण के तत्व :-

1) एकीकृत न्यायपालिका - सर्वोच्च न्यायालय अंतिम न्यायाकार एवं संविधान का संरक्षक घोषित।

2) आपातकाल - इसके तहत अनुच्छेद 352, 356 एवं 360 के द्वारा केंद्र को अस्थायी सशक्त बनाया गया है।

3) केंद्र राज्य संबंध - संघ, सभ्यता सूची पर केंद्र प्रभुत्व।

4) कठोर, कठिना संविधान, एकीकरण को संकेतित करता है।

5) सशक्त केंद्र, एकीकृत संविधान, कठिन भारतीय क्षेत्रों, राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव अदि तत्व संविधान की एकात्मकता को संकेतित करते हैं।

H

भारत की आंतरिक सुरक्षा एक अहम पहलू है जिसे उ तहत अर्थव्यवस्था के विकास का सम्बन्ध सुरक्षात्मक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है।

यह एक आपातकाल परिस्थितियों में अपनी दुर्बल क्षेत्र सुरक्षात्मक एवं मानवीय जीवन बचाने के तत्वावृत्त प्रयास करते हैं। यह एक मुख्यतः केंद्र के अधीन है एवं मूलभूत संरक्षण के अन्तर्गत सम्बन्धित है। इन सैन्य बलों के माध्यम से प्रमुख स्थानों, परिसरों, आपदाओं एवं आर्थिकों में घटित होने वाले विदेशी, देशी अराजकत्वों से सुरक्षा प्रदान करते हैं।

निश्चित ही इसमें तकनीक एवं प्रशिक्षण से क्षेत्र बलों का निर्माण किया जा सकता है।



प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
 (Mains Answer Sheet)

प्रश्न संख्या

5

यह अधिनियम संसद द्वारा 26 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। जिसके अन्तर्गत घरेलू हिंसा से तात्पर्य किसी भी महिला के प्रति शारीरिक, मानसिक, वाचिक, भावनात्मक प्रताड़ना शामिल है। प्रमुख प्रावधान :-

1) उपर्युक्त प्रताड़ना के तहत भारतीय, धर्मरक्षक, अपराधी शामिल हैं जो हिंसा के तहत माने जायेंगे।

श्रवण से सुरक्षा हेतु एक अधिकारी या एनजीओ को महिला हेतु नियुक्त किया जा सकता है।

2) जिसे की प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय में शिकायत

4) अपराध संज्ञेय-असंज्ञेय दोनों श्रेणी में एवं दोषी व्यक्ति को 3 साल की कैद या 20000 जुर्माना या दोनों का आरोपण।

6

संविधान का बुनियादी ढांचा अर्थात् जो संविधान के मूल भावना एवं उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। इसके अन्तर्गत मूल अधिकारों का उद्देश्य, केन्द्र राज्य शक्ति वितरण, न्यायालय स्वतंत्रता, प्रस्तावना का मूल भाव, संसद कानून निर्माण प्रक्रिया, आदि हर एक शामिल हैं।

केशवानंद भारती वाह (1973) के अन्तर्गत संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन की गताहिका निर्णय दिया गया था।



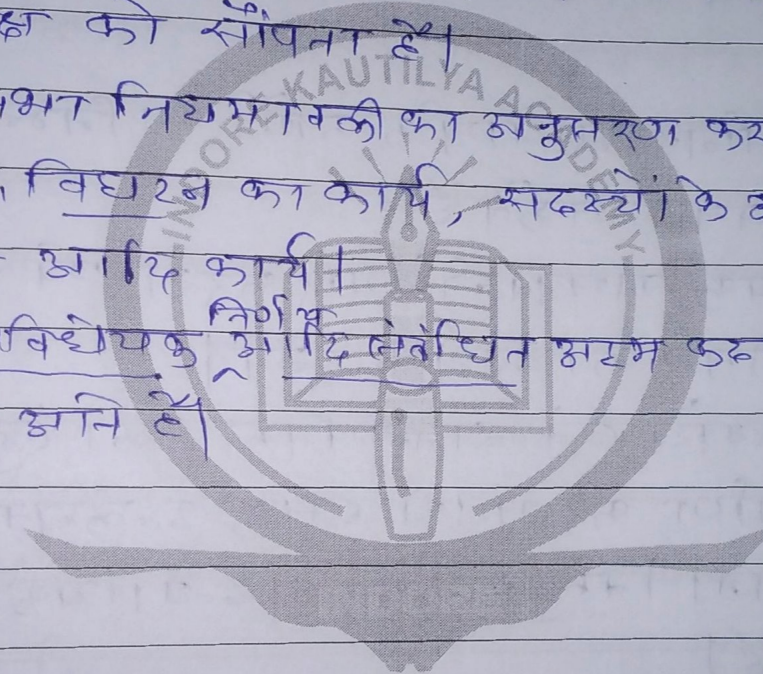
लोकसभा अद्वयक्ष

लोकसभा का ही निर्वाचित सदस्य होता है जिसे सदन के बहुमत से अद्वयक्ष पद निर्वाचित किया जाता है। इससे संबंधित प्रमुख प्रावधान :

1) संयुक्त अधिवेशन की अद्वयक्षता करता है (अनु० 110)
2) संसदीय कार्यपालिका, संचालन एवं बैठकों संबंधी प्रावधानों का संचालन करता है।

3) अद्वयक्ष सदस्य के तौर पर शपथ एवं आयना तथा अन्य उपाद्वयक्ष को सौंपता है।

4) लोकसभा नियमवली का अनुमरण करना, सदन के स्वागन, विद्यरन का कार्य, सदस्यों के आचरणों पर नियंत्रण आदि कार्य।
यन विद्येयकु निर्वाचन आदि संबंधित अरुम उरुम अद्वयक्ष के अन्तर्गत आते हैं।



मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

2 B

संविधान में अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग देश में निर्वाचन एवं इससे संबंधित नियमावली व अन्य प्रावधानों हेतु एक निकाय है।

यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष सहित अन्य 2 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक छिपक हेतु पात्र होते हैं।

निर्वाचन आयोग के कार्यों को निम्न लिखित बिन्दुओं के तहत समझा सकते हैं :-

1) निर्वाचक नामावली तैयार करना एवं चुनाव क्षेत्रों का परिभाषन का कार्य करना।

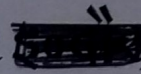
2) उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों हेतु आचारसंहिता का निर्माण करना एवं इसके उल्लंघन पर कठोर काम उठाना। वस्तुतः इसे अर्द्धन्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं।

3) दलों को चुनाव चिन्ह अंकाएँ आवंटन करना।

4) निम्नलिखित व्यवस्थाएँ एवं राजनीतिक प्रवृत्तियों एवं अपराधीकरण को रोकना।

5) चुनावों की तिथि, समय एवं दली संधर्भ में नियमावली तैयार करना।

6) पीठासीन अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों की चुनावों में ड्यूटी का निर्धारण करना।



प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

इन तमाम कार्यों के आधार पर देश में चुनाव संपन्न करने का मुख्य जिम्मेदार आयोग है परन्तु इसमें कुछ शब्दोचनात्मक तत्व मौजूद हैं :

- 1) निर्वाचन आयोग में कॉलेजियम व्यवस्था का अभाव एवं राजनीति से प्रेरित होने के तत्व
- 2) प्रणति: निष्पक्षता एवं जवाबदेहिता का अभाव जिसके कारण समय-समय पर आयोग पर पक्षीकरण के आरोप विपक्षी दलों द्वारा लगाये जाते रहते हैं।

समक्षिा में चुनाव सुधार हेतु की कई कदम 2000 से पूर्व एवं पश्चात उठाये गए हैं :

- 1) ईमीएम प्रशीन का प्रयोग एवं वर्तमान में नए वीवीपीएटी प्रशीन का प्रयोग।
- 2) चिंकू वृष के बूझ का निर्माण जो केवल महिला कार्यकर्ता की मौजूदगी होगी।
- 3) चुनावी खर्च व चंदा 20000 से कम 2000 तक सीमित किया गया।

4) नोरा जैसे कदम यदि सराहनीय हैं। इसके साथ ही चुनाव सुधारवादी अन्य कदमों को उठाये जाने की आवश्यकता है -

- 1) एक देश एक चुनाव की संकल्पना जिसमें लोकसभा विधानसभा चुनाव एक ही समय संपन्न करना
- 2) राजनीतिक संपत्ति को भारतीयार्ड के दायरे में लाना।

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

3) राज्य द्वारा चुनावी चंडे पर पूर्णतः रोक
4) पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता सुनिश्चित करने
जैसे अन्य कदम उठाना।

निष्कर्षतः चुनाव आयोग एक वैधानिक
संस्था है अतः आलोचनाओं के साथ सुधारवादी
उपाय दिये जाने चाहिए ताकि निस्पक्ष लोकतंत्र की
स्थापना हो।





संविधान में भाग-4 के अन्तर्गत अनुच्छेद 33 से 51 तक नीतिनिदेशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। यह तत्व राज्य के लोककल्याणकारी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्मित एवं संविधान में शामिल किये गए हैं। इन तत्वों की अंश विशेषताएं निम्न हैं:

यह राज्य द्वारा समर्थित होते हैं यद्यपि न्यायपालिका के अन्तर्गत वाह योग्य नहीं हैं अर्थात् इनके उल्लंघन पर न्यायपालिका नहीं जाया जा सकता।

यह राज्य में लोककल्याणकारी योजनाओं एवं सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करने हेतु जारी प्रदान करते हैं।

इनमें संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है अर्थात् बुनियादी ढांचे की भावना पर जोर न पड़े।

यह राज्य को विकासात्मक एवं संतुलनकारी आकार प्रदान करने में मदद करते हैं।

नीतिनिदेशक तत्वों को मुख्यतः राष्ट्रीवादी, समाजवादी, आर्थिक एवं उदारवादी अवधारणा के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। प्रमुख नीतिनिदेशक तत्व निम्नलिखित हैं:

1) अनुच्छेद 39 के तहत समान कार्य हेतु समान वेतन की संकल्पना।

2) अनुच्छेद 34 के तहत एक समान नागरिक संहिता की अवधारणा।

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

3) अनुच्छेद 40 - ग्राम सभा की स्थापना

4) इसमें कुटीर लघु उद्योग को प्रोत्साहन एवं संवर्धन दिए जाने का प्रावधान

5) अनुच्छेद 48 - पर्यावरण, वन संरक्षण एवं जैव विविधता संरक्षण हेतु प्रोत्साहित करना

6) अनुच्छेद 1 - अन्तर्राष्ट्रीय संधियों का सही तौर पर क्रियान्वयन किया जाएगा।

7) अनुसूचित जाति, अनुसूचित के कल्याण एवं उन्नयन संबंधी प्रावधान किए जाने चाहिए।

8) महिलाओं के क्षमतिकरण एवं संवर्धन हेतु

9) उद्योगों को संवर्धन एवं एक समान नीति का अनुसरण करना।

निश्चित ही यह तत्व नागरिकों के ऊपर बाध्यकारी नहीं है परन्तु इनके अनुसार नीतियों का क्रियान्वयन राज्य देश के हित में है।

जनसहभागिता से तात्पर्य है शासन प्रशासन के स्तर पर उनकी नीतियों के निर्माण व क्रियान्वयन में नागरिकों को शामिल कर राष्ट्रम उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता।

किसी भी देश में निर्णय प्रक्रिया के स्तर पर नागरिकों को शामिल कर उन्हें देश के विकास की धारा से जोड़ा जा सकता है - इसके तहत

1) नीतियों के निर्माण व क्रियान्वयन - लोकपाल, भ्रष्टाचार संबंधित कानून निर्माण में जनभागीदारी से सरकारात्मक परिणाम सामने आये हैं।

2) नीतियों के तहत शासन व जनता में संवाद -

जनसहभागिता से संवाद सुनिश्चित कर परस्पर सहयोग व विश्वास की भावना को बल मिलता है साथ ही समस्या निवारण हेतु बुझाव व जनता को प्रत्यक्ष कोकृतक का अनुभव होता है।

निश्चित ही नागरिकों की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी सिर्फ भाविक व शारीरिक क्षम से ही नहीं बल्कि समस्त विकास से है जब नागरिक उत्तरदायित्व से युक्त होंगे तभी वास्तविक भागीदारी सामने परिलक्षित होगी।

प्रश्न
संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

जन सहभागिता / नागरिक भागीदारी का

महत्व:

- जनसाधारण के भीतर उद्देश्यशक्ति उत्पन्न करना।
- समुदाय में उपलब्ध संसाधन पहचान एवं विकास करना।
- समुदाय में स्थानीय नेतृत्व प्रोत्साहन देना ताकि अन्य को प्रेरणा मिल सके।
- यह वास्तविक लोकतंत्र की पूर्णता का माध्यम हैं।
- प्रशासनिक नेतृत्व प्राप्त करना।
- पारदर्शिता, जवाबदेहिता सुनिश्चित।
- नागरिकों में कर्तव्य निर्वहन भावना का विकास।
- उत्तरदायित्व गृहण करने की समता का विकास।
- निष्कर्षतः समूह, संगठन माध्यम से जनता को विकास प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है।